पत्र संख्या–20एम०–वि०प०(तारांकित)–14 / 2023

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

सूर्य किशोर प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **श्री जनक राम, माननीय स० वि० प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 205वाँ सत्र में पूछा जानेवाला ऑनलाईन तारांकित प्रश्न संख्या–1 / 205 / 185, दिनांक–02.11.2023 के स्थानान्तरण के संबंध में।**

प्रसंगः– बिहार विधान परिषद् सचिवालय से ऑनलाईन तारांकित प्रश्न संख्या–1 / 205 / 185, दिनांक–02.11.2023 द्वारा प्राप्त।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विषयांकित प्रश्न **योजना एवं विकास विभाग** से संबंधित है।

अतएव बिहार विधान परिषद् सचिवालय से प्राप्त ऑनलाईन प्रश्न की छायाप्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि वांछित उत्तर बिहार विधान परिषद् सचिवालय को ससमय भेजते हुये उसकी प्रति संसदीय कार्य विभाग एवं वित्त विभाग को भी देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह० / –
(सूर्य किशोर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– **/वि०, पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को तारांकित ऑनलाईन प्रश्न संख्या–**1 / 205 / 185** के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –
(सूर्य किशोर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– /वि०, पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(सूर्य किशोर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 9905 /वि०, पटना, दिनांक– 06-11-2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, से अनुरोध है कि स्थानान्तरण संबंधी ऑनलाईन अपलोडिंग सुनिश्चित की जाए।

6/11/23

(सूर्य किशोर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

Bihar Vidhan Parishad Question

1/205/185

कानून बनाने का विचार कबतक

26/10/2023 02/11/2023

*1/205/185 श्री जनक राम(मनोनीत)

वित्त विभाग

(क) क्या यह सही है कि योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के SCSP TSP के दिशानिर्देश के अनुसार SC/ST की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2018-19 में CAG Report के अनुसार बिहार सरकार ने SCSP बजट के 8800 करोड़ रुपए से अधिक का उपयोग बड़े हाइवे, बांध, मेडिकल कॉलेज एवं बिजली कम्पनियों को लोन अनुदान देने पर खर्च किया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब के तर्ज पर SCSP TSP के संचालन के लिए कानून बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?